


25.11.20

पत्रावली प्रस्तुत की गई। वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण ने न्यायालय के सप्रसन्न निवेदन किया कि उनके जवाब को ही बहस के रूप में कन्सीडर किया जावे।


प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी भी उक्त भूमि में सहखातेदार हैं तथा आज दिनांक तक प्रश्नगत भूमि के सहकप्तारों के बीच जोतों का विभाजन नहीं हुआ है।

(i) चूंकि प्रार्थी प्रश्नगत भूमि का रिकॉर्ड टिनेन्ट है, अतः प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है।

(ii) चूंकि प्रश्नगत भूमि के जोतों का बंटवारा नहीं हुआ है, अतः यदि अप्रार्थीगण द्वारा किलो निश्चित किलाजत का बंटवारा बैचान कर दिया जाता है, तो असुविधा प्रार्थी को होगी। अतः सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।

(iii) चूंकि प्रार्थी ने घरेलू लिखित बंटवारा नामा के आधार पर जोतों के विभाजन का अनुतोष चाहा है, यदि अप्रार्थीगण द्वारा अनुतोष में प्र  द्वारा चाहे गए किलों का बैचान कर दिया जाता है एवं वाद बदा के पक्ष में डिक्री हो जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णवीच क्षति होगी।

फलतः अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निधिरित करने हेतु विचारणीय तीनों बिन्दु प्रार्थी के पदा में हैं, अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 श.का. अ. सतद्वारा स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसना वाद पाबंद किया जाता है कि वे चक 72 जोबी तहसील अनूपगढ़ के प.नं. 268/436 मु.नं. 20 के किला नं. 1 ता 25 का 6.200 है. कमा 05 कृषि भूमि के किन्ही विशिष्ट किलाजात को खन, बँच अथवा अन्यथा हस्तान्तरित न करें। फैसला सरे इजलास जुगाया गया।


25/11/20